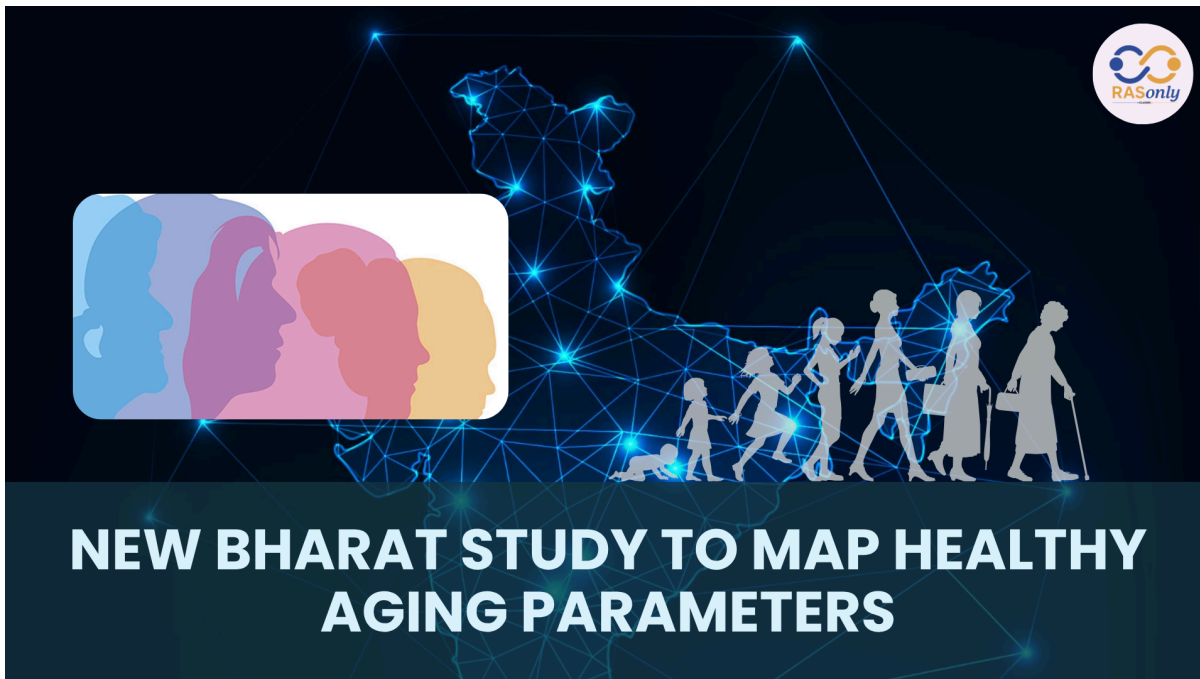


New BHARAT Study to Map Healthy Aging Parameters



Category: National, Governance

BHARAT (Biomarkers of Healthy Aging, Resilience, Adversity, and Transitions) is the first nationwide study truly large in scale addressing ageing in India, led by IISc Bengaluru, that attempts to generate a scientific baseline of ageing parameters of Indians. It will combine biomarkers, genomics, proteomics and artificial intelligence to investigate the nature of ageing differently in Indian people due to genetics, lifestyle, and environment. This research questions the universal nature of Western standards of diagnostics. It is hoped that by charting out India specific ageing indicators, misdiagnosis can be minimized and better health intervention can be achieved. It is the first step towards the development of context-sensitive and equitable models of healthcare among the ageing population in India.

Why in the news?

- India is in the process of passing through the ageing stage of a demographic transition due to which by 2050 almost one-fifth of the Indians will be aged 60+.
- Nevertheless, health diagnostics is still pegged in western biomarkers which do not necessarily reflect the biological norms in India.
- The proposed BHARAT is filling this gap by developing an Indian reference database of ageing indicators that can provide scientific clarity regarding what should be known as normal ageing in the Indian setting.

Key Details for RAS Mains

Central Goals of BHARAT Study

- Determine Indian specific healthy ageing biomarkers.
- Close diagnostic gap that exists because of the use of Western thresholds.



<https://t.me/+9dLgyy8BipQ3YjB>



HYPERLINK
["https://rasonly.com"](https://rasonly.com)
<https://rasonly.com>

- The creation of the Bharat Baseline aka an India specific health baseline standard.
- Use AI/ML as a tool to unravel a vast amount of multidimensional bio-environmental interactions forming the backbone of the ageing process.
- Give early warning signs of organ specific deterioration prior to disease.
- Empower forecast health care services such as dementia, heart problems, and Parkinson.

Key highlights

Feature	Description
Lead Institution	Indian Institute of Science (IISc), Bengaluru
Study Name	BHARAT (Biomarkers of Healthy Aging, Resilience, Adversity, and Transitions)
Nature of Study	Multidisciplinary: Genomic, proteomic, metabolic, and environmental
Launch Year	2023-24
Methodologies Used	Large-scale sample analysis, AI/ML modelling, predictive simulations
Collaborators	Indraprastha Institute of Information Technology (IIIT-D), National Centre for Biological Sciences (NCBS)

Scientific Significance

- The Chronological Age is not the same as Biological Age: Years of age can imply varied degrees of organ health or exposure to risk of morbidity and mortality, based upon genetic makeup, lifestyle, and conditions during early life.
- Levels of CRP and Vitamin Deficiency Mislabels: C-reactive protein (CRP), cholesterol vitamin D & B12 levels are measured differently in Indians.
- Ethnicity Specific Markers: western markers can produce overdiagnosis (the normal being labelled as diseased) or underdiagnosis (omission of risk factors).

Policy and Social Implications

- **Health Equity in Ageing Population**
 - India needs to develop health policies based on age related susceptibility taking into consideration the Indian context.
 - Ageing-related decline can be detected early thereby reducing the burden and costs exerted on the healthcare system.
- **Guidelines on National Healthcare**
 - BHARAT can impact on the standards of ICMR, NITI Aayog and the Health Ministry in reshaping the norms of the biomarkers in the clinical practice of India.
- **Age-Ready Infrastructure**
 - The post-capitalist geriatrics, pensions, insurance and disability conventions in older populations could be based on the results.
- **The Priority of AI Public Health Role**
 - AI will assist in predicting the age of organs, respond to treatment virtually, and deem at-risk persons even before they are unwell.

Challenges



<https://t.me/+9dLgyy8BipQ3YjB>



HYPERLINK
["https://rasonly.com"](https://rasonly.com)
<https://rasonly.com>

- Sampling Diversity: India is genetically, dietarily and lifestyle diverse, which is a sampling problem.
- Scalability / Funding: There must be long term funding by the public and philanthropies.
- Public engagement: It is hard to find healthy people to recruit them and lacking awareness and mistrust about how data is going to be used.
- Ethical Implications: Informed consent, privacy of genetic information, fair use of findings, and results should be guaranteed.

Global Comparison

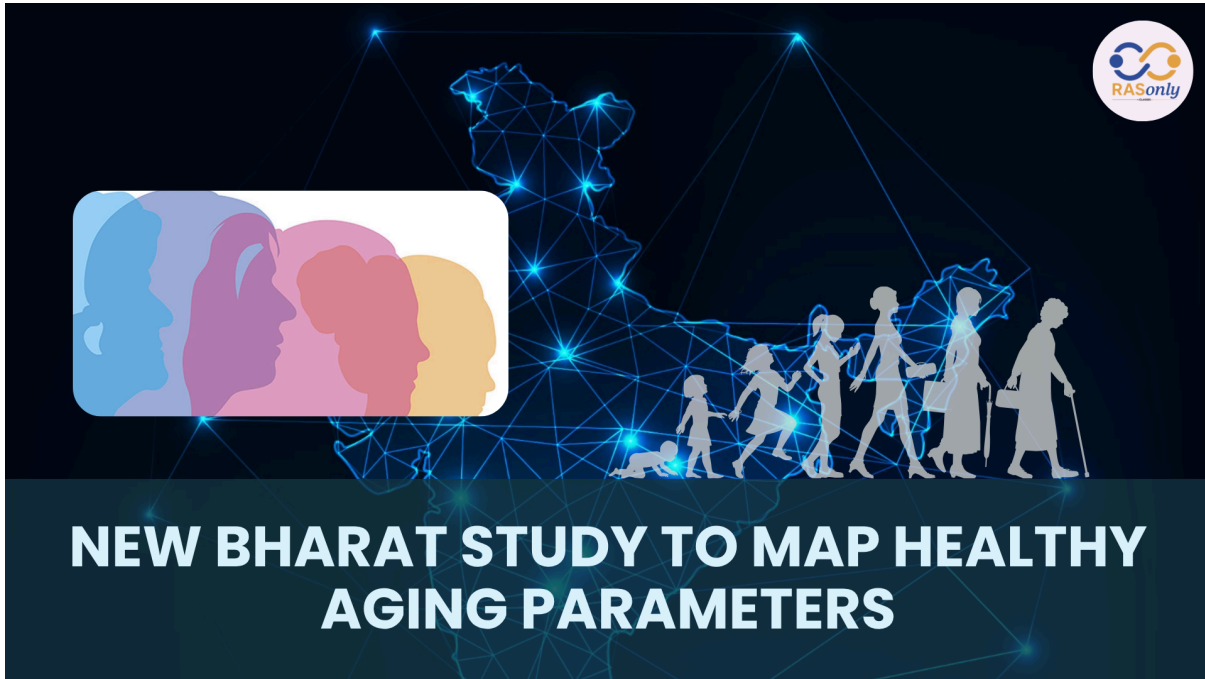
Country	Project	Focus
USA	Framingham Heart Study	Cardiovascular risk in ageing
UK	UK Biobank	Genomics & public health
China	CHARLS	Elderly health and socio-economic survey
India	BHARAT	Biomarkers of healthy ageing in Indian populations

Conclusion

The BHARAT study is a revolutionary step absent from the one-fit-all healthcare to the personalized and India specific ageing science. It is an example of how the Global South could establish control over biomedical research and take away the space occupied by Eurocentric systems. Provided it becomes a success, BHARAT has the potential to transform the way people are diagnosed, promote healthy ageing policy, and enhance clinical management of the ageing population in India, thus guaranteeing not only longer, but also healthier life to millions.



स्वस्थ उम्र बढ़ने के मापदंडों का मानचित्रण करने के लिए नया भारत अध्ययन



भारत (स्वस्थ उम्र बढ़ने, लचीलापन, प्रतिकूलता और संक्रमण के बायोमार्कर) भारत में उम्र बढ़ने को संबोधित करने वाला पहला राष्ट्रव्यापी अध्ययन है, जिसका नेतृत्व IISc बैंगलुरु द्वारा किया गया है, जो भारतीयों की उम्र बढ़ने के मापदंडों का एक वैज्ञानिक आधार तैयार करने का प्रयास करता है। यह बायोमार्कर, जीनोमिक्स, प्रोटीओमिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिलाकर भारतीय लोगों में आनुवंशिकी, जीवनशैली और पर्यावरण के कारण अलग-अलग उम्र बढ़ने की प्रकृति की जांच करेगा। यह शोध निदान के पश्चिमी मानकों की सार्वभौमिक प्रकृति पर सवाल उठाता है। यह आशा की जाती है कि भारत के विशिष्ट उम्र बढ़ने के संकेतकों को चार्ट करके, गलत निदान को कम किया जा सकता है और बेहतर स्वास्थ्य हस्तक्षेप प्राप्त किया जा सकता है। यह भारत में वृद्ध आबादी के बीच स्वास्थ्य सेवा के संदर्भ-संवेदनशील और न्यायसंगत मॉडल के विकास की दिशा में पहला कदम है।

चर्चा में क्यों?

- भारत जनसांख्यिकीय परिवर्तन के वृद्धावस्था चरण से गुजर रहा है, जिसके कारण 2050 तक लगभग पांचवां भारतीय 60 वर्ष से अधिक आयु का हो जाएगा।
- फिर भी, स्वास्थ्य निदान अभी भी पश्चिमी जैव-चिह्नों पर आधारित है, जो आवश्यक रूप से भारत के जैविक मानदंडों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।
- प्रस्तावित भारत इस अंतर को भर रहा है, तथा इसके लिए वह वृद्धावस्था संकेतकों का एक भारतीय संदर्भ डेटाबेस विकसित कर रहा है, जो भारतीय परिवेश में सामान्य वृद्धावस्था के बारे में वैज्ञानिक स्पष्टता प्रदान कर सकता है।

आरएस मुख्य परीक्षा के लिए मुख्य विवरण

भारत अध्ययन के केंद्रीय लक्ष्य

- भारतीय विशिष्ट स्वस्थ आयुवृद्धि बायोमार्करों का निर्धारण करना।
- पश्चिमी थ्रेसहोल्ड के उपयोग के कारण मौजूद निदान संबंधी अंतर को कम करना।
- भारत बेसलाइन अर्थात भारत विशिष्ट स्वास्थ्य बेसलाइन मानक का निर्माण।
- उम्र बढ़ने की प्रक्रिया की रीढ़ बनाने वाली बहुआयामी जैव-पर्यावरणीय अंतःक्रियाओं की विशाल मात्रा को उजागर करने के लिए एक उपकरण के रूप में एआई/एमएल का उपयोग करें।



- रोग से पहले अंग विशेष में गिरावट के बारे में प्रारंभिक चेतावनी संकेत दें।
- मनोभंश, हृदय संबंधी समस्याओं और पार्किंसन जैसी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का पूर्वानुमान लगाना।

मुख्य बातें

विशेषता	विवरण
प्रमुख संस्थान	भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु
अध्ययन का नाम	भारत (स्वस्थ उम्र बढ़ने, लचीलापन, प्रतिकूलता और संक्रमण के बायोमार्कर)
अध्ययन की प्रकृति	बहुविषयक: जीनोमिक, प्रोटीओमिक, चयापचय और पर्यावरण
लॉन्च वर्ष	2023-24
प्रयुक्त पद्धतियां	बड़े पैमाने पर नमूना विश्लेषण, एआई/एमएल मॉडलिंग, पूर्वानुमानात्मक सिमुलेशन
सहयोगियों	इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी-डी), राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र (एनसीबीएस)

वैज्ञानिक महत्व

- कालानुक्रमिक आयु जैविक आयु के समान नहीं हैं: आयु के वर्ष, आनुवंशिक संरचना, जीवनशैली और प्रारंभिक जीवन के दौरान स्थितियों के आधार पर, अंगों के स्वास्थ्य या रुग्णता और मृत्यु दर के जोखिम के विभिन्न स्तरों को दर्शा सकते हैं।
- सीआरपी और विटामिन की कमी के स्तर गलत लेबल: सी-रिएक्टिव प्रोटीन (सीआरपी), कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी और बी 12 के स्तर भारतीयों में अलग-अलग तरीके से मापे जाते हैं।
- जातीयता विशिष्ट मार्कर: पश्चिमी मार्कर अति निदान (सामान्य को रोगग्रस्त के रूप में चिह्नित किया जाना) या अल्प निदान (जोखिम कारकों की अनदेखी) उत्पन्न कर सकते हैं।

नीति और सामाजिक निहितार्थ

- वृद्ध जनसंख्या में स्वास्थ्य समानता
 - भारत को भारतीय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए आयु संबंधी संवेदनशीलता के आधार पर स्वास्थ्य नीतियां विकसित करने की आवश्यकता है।
 - उम्र बढ़ने से संबंधित गिरावट का शीघ्र पता लगाया जा सकता है, जिससे स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर पड़ने वाले बोझ और लागत को कम किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा पर दिशानिर्देश
 - भारत के नैदानिक अभ्यास में बायोमार्करों के मानदंडों को नया रूप देने में भारत आईसीएमआर, नीति आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों पर प्रभाव डाल सकता है।
- आयु-तैयार बुनियादी ढांचा
 - वृद्ध आबादी में उत्तर-पूजीवादी वृद्धावस्था, पेंशन, बीमा और विकलांगता संबंधी रुढ़ियाँ परिणामों पर आधारित हो सकती हैं।
- एआई सार्वजनिक स्वास्थ्य भूमिका की प्राथमिकता
 - एआई अंगों की आयु का अनुमान लगाने, आभासी रूप से उपचार पर प्रतिक्रिया करने, तथा जोखिम वाले व्यक्तियों को उनके अस्वस्थ होने से पहले ही पहचानने में सहायता करेगा।

चुनौतियां

- नमूनाकरण विविधता: भारत में आनुवंशिक, आहार और जीवनशैली विविधतापूर्ण है, जो एक नमूनाकरण समस्या है।
- मापनीयता/वित्तपोषण: जनता और परोपकारी संस्थाओं द्वारा दीर्घकालिक वित्त पोषण होना चाहिए।



- सार्वजनिक सहभागिता: इसमें भर्ती के लिए स्वस्थ लोगों को ढूंढना कठिन है, तथा डेटा का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा, इस बारे में जागरूकता और अविश्वास का अभाव है।
- नैतिक निहितार्थ: सूचित सहमति, आनुवंशिक जानकारी की गोपनीयता, निष्कर्षों और परिणामों के उचित उपयोग की गारंटी दी जानी चाहिए।

वैश्विक तुलना

देश	परियोजना	केंद्र
हिरन	फ्रामिंगम हार्ट स्टडी	वृद्धावस्था में हृदय संबंधी जोखिम
यूके	यूके बायोबैंक	जीनोमिक्स और सार्वजनिक स्वास्थ्य
चीन	CHARLS	वृद्धजनों के स्वास्थ्य एवं सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण
भारत	भारत	भारतीय आबादी में स्वस्थ उम्र बढ़ने के बायोमार्कर

निष्कर्ष

भारत अध्ययन एक क्रांतिकारी कदम है जो सभी के लिए एक जैसी स्वास्थ्य सेवा से हटकर व्यक्तिगत और भारत-विशिष्ट वृद्धावस्था विज्ञान की ओर ले जाता है। यह इस बात का उदाहरण है कि कैसे वैश्विक दक्षिण जैव चिकित्सा अनुसंधान पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है और यूरोसैंट्रिक प्रणालियों द्वारा कब्जा की गई जगह को हटा सकता है। बशर्ते यह सफल हो जाए, भारत में लोगों के निदान के तरीके को बदलने, स्वस्थ वृद्धावस्था नीति को बढ़ावा देने और भारत में वृद्ध आबादी के नैदानिक प्रबंधन को बढ़ाने की क्षमता है, जिससे लाखों लोगों को न केवल लंबा, बल्कि स्वस्थ जीवन भी मिल सकता है।

“Sabrang”: Hyderabad’s Landmark Transgender Clinic Relaunch



Category: National



<https://t.me/+9dLgyy8BipQ3YjB>



HYPERLINK
["https://rasonly.com"](https://rasonly.com)
<https://rasonly.com>

The first health clinic India-led by trans people, the Mitr Clinic, that had closed after USAID froze its funding, reopened in Hyderabad as the Sabrang Clinic with funding through Tata Trusts. This is one step toward higher inclusivity and community-based healthcare of transgender individuals. Since opening its doors in 2021, the clinic, whose entire staff is part of the trans community, has received more than 3,000 patients. Sabrang which translates to all colours is an indication of diversity and dignity in accessing healthcare. It has created a precedent of comprehensive social justice and health in India.

Why in the news?

- Access to healthcare is a big challenge to the transgender community in India because it is characterized by discrimination and stigma; this is coupled with a non-sensitized approach to offering gender-affirmative care.
- In 2021, Mitr Clinic appeared to be a radical project: a clinic with trans staff and trans leadership, a clinic that had never existed in the country before.
- These gains were at risk of becoming surmounted when it was forced to close in early 2025 because of financial support problems outside the organization.
- Nevertheless, its restoration appears as a strong and community-empowered people initiative in terms of public health improvement.

Key Details for RAS Mains

Feature	Description
Name	Sabrang Clinic (formerly Mitr Clinic)
Location	Narayanguda, Hyderabad
Managed by	Members of the transgender community
Supported by	Tata Trusts (from May 2025)
Earlier Support	USAID (till Jan 2025)
Beneficiaries	Over 3,000 transgender persons since 2021
Meaning of 'Sabrang'	"All colours" — symbol of inclusivity and diversity

Significance

- **Access & Dignity in Healthcare**
 - Transgender individuals tend to be neglected medically and discriminated against and without the proper health care. At Sabrang, the environment is secure, respectful and specialised.
- **Community-Led Model**
 - Allows the transgender to be boss, administrator and healer, which generates trust in the community.
 - Covers mental health, STI/STD treatment, hormone treatment and overall health.
- **Sustainability By Philanthropy**
 - Illustrates how businesses (such as corporate philanthropy e.g. Tata Trusts) can intervene to safeguard important and vulnerable health programs.



- Facilitates the de-politicization of healthcare financing to disadvantaged populations.
- **Model of Replication**
 - Offers a roadmap of trans-inclusive health resources on state-level.
 - It is in accordance with the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 that requires placing no restrictions on healthcare.

Issues of Transgender Healthcare in India

- Inadequacy of gender-neutral wards and staff in the public hospitals.
- Harassment and misgendering in the medical setting.
- No specific national health scheme even though the Act provides it.
- Social and governmental challenges of getting identity papers to get services.

Way Forward

- Mainstream the Sabrang model, in terms of both National Health Mission and State Health Policies.
- Encompass gender-specific care and modules trans-based teaching into the medical curriculum.
- Promote state sponsored clinics both in the urban and semi-urban regions.
- Fill the gaps with the stable non-conditional funding based on the patterns of the public-private partnerships foundation.
- Conduct trans health awareness and destigmatisation IEC campaigns.

Conclusion

The reintegration of the first transgender clinic in India as Sabrang is not only a symbolic act, but a structural aspect as well. It helps close the life or death healthcare gap between one of the most marginalized communities in India and a more comprehensive idea of the health of the population. It restructures dignity, access, and equality in the Indian health system by empowering trans persons to be the leaders of the health provision. States should learn to replicate and mass reciprocate this design to ensure that nobody will be left behind on the journey to realizing universal health coverage.

“सबरंग”: हैदराबाद का ऐतिहासिक ट्रांसजेंडर क्लिनिक पुनः शुरू



“SABRANG”: HYDERABAD'S LANDMARK TRANSGENDER CLINIC RELAUNCH

ट्रांस लोगों द्वारा संचालित भारत का पहला स्वास्थ्य क्लिनिक, मित्र क्लिनिक, जो USAID द्वारा इसके वित्तपोषण पर रोक लगाने के बाद बंद हो गया था, टाटा ट्रस्ट के माध्यम से वित्तपोषण के साथ हैदराबाद में सबरंग क्लिनिक के रूप में फिर से खुल गया। यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए उच्च समावेशिता और समुदाय-आधारित स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक कदम है। 2021 में अपने दरवाजे खोलने के बाद से, क्लिनिक, जिसका पूरा स्टाफ ट्रांस समुदाय का हिस्सा है, ने 3,000 से अधिक रोगियों को प्राप्त किया है। सबरंग जिसका अर्थ है सभी रंग, स्वास्थ्य सेवा तक पहुँचने में विविधता और गरिमा का संकेत है। इसने भारत में व्यापक सामाजिक न्याय और स्वास्थ्य की एक मिसाल कायम की है।

चर्चा में क्यों?

- भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह भेदभाव और कलंक से घिरा हुआ है; इसके साथ ही लिंग-सकारात्मक देखभाल प्रदान करने के लिए गैर-संवेदनशील दृष्टिकोण भी मौजूद है।
- 2021 में, मित्र क्लिनिक एक क्रांतिकारी परियोजना प्रतीत हुई: ट्रांस स्टाफ और ट्रांस नेतृत्व वाला एक क्लिनिक, एक ऐसा क्लिनिक जो देश में पहले कभी अस्तित्व में नहीं था।
- ये लाभ तब खत्म हो जाने का खतरा था जब संगठन के बाहर वित्तीय सहायता संबंधी समस्याओं के कारण इसे 2025 की शुरुआत में बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- फिर भी, इसका पुनरुद्धार सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार के संदर्भ में एक मजबूत और समुदाय-सशक्त लोगों की पहल के रूप में दिखाई देता है।

आरएस मुख्य परीक्षा के लिए मुख्य विवरण

विशेषता	विवरण
नाम	सबरंग क्लिनिक (पूर्व में मित्र क्लिनिक)
जगह	Narayanguda, Hyderabad
द्वारा प्रबंधित	ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य
द्वारा समर्थित	टाटा ट्रस्ट्स (मई 2025 से)



<https://t.me/+9dLgyv8BipQ3YjB>



HYPERLINK
["https://rasonly.com"](https://rasonly.com)
<https://rasonly.com>

पहले का समर्थन	यूएसएआईडी (जनवरी 2025 तक)
लाभार्थियों	2021 से अब तक 3,000 से अधिक ट्रांसजेंडर व्यक्ति
‘सबरंग’ का अर्थ	“सभी रंग” - समावेशिता और विविधता का प्रतीक

महत्व

- स्वास्थ्य सेवा में पहुंच और गरिमा
 - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को चिकित्सकीय रूप से उपेक्षित किया जाता है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है और उन्हें उचित स्वास्थ्य देखभाल नहीं मिलती। सबरंग में, वातावरण सुरक्षित, सम्मानजनक और विशिष्ट है।
- समुदाय-नेतृत्व मॉडल
 - यह ट्रांसजेंडर को बॉस, प्रशासक और उपचारक बनने की अनुमति देता है, जिससे समुदाय में विश्वास उत्पन्न होता है।
 - मानसिक स्वास्थ्य, एसटीआई/एसटीडी उपचार, हार्मोन उपचार और समग्र स्वास्थ्य को कवर करता है।
- परोपकार द्वारा स्थिरता
 - यह दर्शाता है कि किस प्रकार व्यवसाय (जैसे कॉर्पोरेट परोपकारी संस्थाएं, जैसे टाटा ट्रस्ट्स) महत्वपूर्ण और कमजोर स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप कर सकते हैं।
 - यह वंचित आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण के गैर-राजनीतिकरण को सुगम बनाता है।
- प्रतिकृति का मॉडल
 - राज्य स्तर पर सर्वसमावेशी स्वास्थ्य संसाधनों का रोडमैप प्रस्तुत किया गया है।
 - यह ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अनुरूप है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा पर कोई प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं है।

भारत में ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य सेवा के मुद्दे

- सार्वजनिक अस्पतालों में लिंग-तटस्थ वार्डों और कर्मचारियों की अपर्याप्तता।
- चिकित्सा क्षेत्र में उत्पीड़न एवं गलत लिंग निर्धारण।
- यद्यपि अधिनियम में इसका प्रावधान है, फिर भी कोई विशिष्ट राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना नहीं है।
- सेवाएँ प्राप्त करने के लिए पहचान पत्र प्राप्त करने की सामाजिक और सरकारी चुनौतियाँ।

आगे बढ़ने का रास्ता

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राज्य स्वास्थ्य नीतियों दोनों के संदर्भ में सबरंग मॉडल को मुख्यधारा में लाना।
- चिकित्सा पाठ्यक्रम में लिंग-विशिष्ट देखभाल और ट्रांस-आधारित शिक्षण मॉड्यूल को शामिल करना।
- शहरी और अर्ध-शहरी दोनों क्षेत्रों में राज्य प्रायोजित क्लीनिकों को बढ़ावा देना।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी फाउंडेशन के पैटर्न के आधार पर स्थिर, बिना शर्त वित्तपोषण के माध्यम से अंतराल को भरना।
- ट्रांस स्वास्थ्य जागरूकता और विकलंकीकरण आईईसी अभियान संचालित करें।

निष्कर्ष

भारत में सबरंग के रूप में पहले ट्रांसजेंडर क्लिनिक का पुनः एकीकरण न केवल एक प्रतीकात्मक कार्य है, बल्कि एक संरचनात्मक पहलू भी है। यह भारत के सबसे हाशिए पर पड़े समुदायों में से एक और आबादी के स्वास्थ्य के बारे में अधिक व्यापक विचार के बीच जीवन या मृत्यु के स्वास्थ्य सेवा अंतर को कम करने में मदद करता है। यह ट्रांस व्यक्तियों को स्वास्थ्य प्रावधान के नेता बनने के लिए सशक्त बनाकर भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली में सम्मान, पहुंच और समानता का पुनर्गठन करता है। राज्यों को इस डिजाइन को दोहराना और बड़े पैमाने पर पारस्परिक रूप से लागू करना सीखना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को साकार करने की यात्रा में कोई भी पीछे न छूट जाए।



Rajasthan

Strengthening of Dental Education in Rajasthan, Reconstitution of State Dental Council



Sector: Health & Medical Education

Subject: Reforms in Dental Education and Public Oral Health in Rajasthan

- Rajasthan government is set to strengthen dental education and related health services in the state.
- Rajasthan Dental Council will be reconstituted under the National Dental Commission Act, 2021.
- Rules under this act will be reviewed for implementation in the state.
- Secretary of Medical Education, Mr. Ambrish Kumar, held a key meeting with members of the National Dental Commission regarding these reforms.
- A detailed report has been ordered on illegal admissions in dental colleges to ensure transparency in the admission process.
- Budget announcements related to dental and oral health services are being reviewed for alignment with state needs.
- A committee will be formed to revise the curriculum by adopting best practices from top dental institutions in India.
- Faculty training programs will be enhanced.
- Proposal to implement a centralized patient data system like IHMS in dental colleges has been discussed.
- Biometric attendance system (AEBAS) will be introduced in affiliated colleges like RUHS and Marwar University for regular monitoring of faculty attendance.



- Continuous education programs for dental practitioners will be introduced.
- Creation of new posts for dental doctors in CHCs, PHCs, trauma centers, district and sub-district hospitals is under consideration.
- Data on sanctioned dental posts from other states will be collected for comparative planning.
- A proposal for a National Oral Health Program specific to Rajasthan will be prepared.

Detailed Explanation for RAS Aspirants (Short Points):

- **Governance Reform:** Implementation of *National Dental Commission Act, 2021* aligns the state with national standards in dental education and regulation.
- **Transparency Measures:** Detailed probe into illegal admissions ensures accountability and fairness in public institutions.
- **Curricular Upgradation:** Curriculum reforms through benchmarking against top institutions promote standardization and skill enhancement.
- **Use of Technology:** Introduction of IHMS and AEBAS reflects e-governance and digitization in medical education and administration.
- **Human Resource Strengthening:** Plan to increase dental posts indicates a step toward improved health infrastructure and service delivery.
- **Budget Alignment:** Reviews of budgetary announcements are aimed at practical and need-based implementation of dental health services.
- **Public Health Focus:** Proposal for a *National Oral Health Program* indicates state's intent to integrate oral health into mainstream healthcare services.

Standard Hindi Translation

क्षेत्र: स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

विषय: राजस्थान में दंत चिकित्सा शिक्षा एवं सार्वजनिक मौखिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

राजस्थान में सुदृढ़ होगी दंत चिकित्सा शिक्षा, होगा राज्य दंत परिषद का पुनर्गठन

- प्रदेश में दंत चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा।
- *राष्ट्रीय दंत आयोग अधिनियम, 2021* के तहत राजस्थान दंत परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा।
- इस अधिनियम के नियमों की राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समीक्षा की जाएगी।
- चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीष कुमार ने इस विषय पर राष्ट्रीय दंत आयोग के सदस्यों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए।
- दंत महाविद्यालयों में अवैध प्रवेश मामलों की जांच हेतु एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए।
- दंत चिकित्सा एवं सार्वजनिक मौखिक स्वास्थ्य से जुड़ी बजट घोषणाओं की समीक्षा की जा रही है।
- पाठ्यक्रम में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जो देश के प्रमुख संस्थानों से बेस्ट प्रैक्टिसेज अपनाएगी।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी मजबूत किया जाएगा।



- दंत महाविद्यालयों में मरीजों की निगरानी के लिए आईएचएमएस जैसी सॉफ्टवेयर प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव।
- आरयूएचएस व मारवाड़ विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में शिक्षकों की उपस्थिति के लिए एईबीएस प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव।
- दंत चिकित्सकों के लिए निरंतर शिक्षा कार्यक्रम चलाने का निर्णय।
- सीएचसी, पीएचसी, ट्रॉमा सेंटर, जिला व उप-जिला अस्पतालों में दंत चिकित्सकों के नए पद सृजित करने पर विचार।
- अन्य राज्यों के स्वीकृत पदों का तुलनात्मक डेटा एकत्र कर योजना बनाई जाएगी।
- राजस्थान के लिए राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश।

RAS अभ्यर्थियों हेतु संक्षिप्त महत्वपूर्ण बिंदु:

- **शासन सुधार:** राष्ट्रीय दंत आयोग अधिनियम, 2021 का कार्यान्वयन केंद्र-राज्य समन्वय का उदाहरण है।
- **पारदर्शिता उपाय:** अवैध प्रवेश की जांच से संस्थानों में जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
- **पाठ्यक्रम उन्नयन:** शीर्ष संस्थानों से तुलना द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** IHMS और AEBAS जैसी प्रणालियां डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देती हैं।
- **मानव संसाधन सशक्तिकरण:** दंत चिकित्सकों के पद सृजन से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी।
- **बजट कार्यान्वयन:** वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार योजना क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाएगा।
- **जन स्वास्थ्य दृष्टिकोण:** मौखिक स्वास्थ्य को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास।

MCQs

Subject: Health & Governance

Topic: Dental Education Reforms in Rajasthan

What act is being implemented for reconstituting the Rajasthan Dental Council?

1. National Medical Commission Act, 2019
2. Indian Dental Act, 1948
3. National Dental Commission Act, 2021
4. Rajasthan Dental Regulation Act, 2022

Answer: 3

Explanation: The Rajasthan Dental Council will be reconstituted under the National Dental Commission Act, 2021.



विषय: स्वास्थ्य एवं शासन

विषयवस्तु: राजस्थान में दंत चिकित्सा सुधार

राजस्थान दंत परिषद के पुनर्गठन के लिए कौन-सा अधिनियम लागू किया जा रहा है?

1. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019
2. भारतीय दंत अधिनियम, 1948
3. राष्ट्रीय दंत आयोग अधिनियम, 2021
4. राजस्थान दंत विनियमन अधिनियम, 2022

उत्तर: 3

व्याख्या: राजस्थान दंत परिषद का पुनर्गठन राष्ट्रीय दंत आयोग अधिनियम, 2021 के अंतर्गत किया जाएगा।

Subject: Public Health Policy

Topic: Oral Health Services in Rajasthan

Which of the following systems is proposed to ensure centralized patient monitoring in dental colleges?

1. PMJAY
2. IHMS
3. AEBAAS
4. eSanjeevani

Answer: 2

Explanation: IHMS-like centralized software is proposed to keep digital records of patients in dental colleges.

विषय: सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति

विषयवस्तु: राजस्थान में मौखिक स्वास्थ्य सेवाएं

दंत महाविद्यालयों में केंद्रीकृत मरीज निगरानी के लिए किस प्रणाली को लागू करने का प्रस्ताव है?

1. पीएम-जय
2. आईएचएमएस
3. आईबीएस
4. ई-संजीवनी

उत्तर: 2

व्याख्या: आईएचएमएस जैसी केंद्रीकृत प्रणाली मरीजों का डेटा रखने हेतु प्रस्तावित की गई है।



Nationwide Campaign on Financial Inclusion and Social Security from July 1 to September 30



Sector: Financial Inclusion & Social Security

Subject: Government Schemes & Banking Access

Summary in Bullet Points:

- The Department of Financial Services, Government of India, is conducting a **nationwide campaign** from **July 1 to September 30, 2025**, focused on **financial inclusion and social security**.
- The campaign aims to provide **access to essential banking, insurance, and pension services** at the **Gram Panchayat level**.
- **Special camps** will be organized in each **Gram Panchayat at least once**, mainly on **Saturdays**.
- Instructions have been issued by **Chief Secretary Shri Sudhansh Pant** to all **District Collectors** for organizing these camps with coordination from the **District Level Bankers Committee (DLBC)**.
- Camps will include participation from **all banks**, and efforts will be made to ensure required **logistical and human resources**.
- Citizens are encouraged to actively participate and **secure their financial well-being** through the campaign.
- **Key focus areas** of the campaign:
 - **Re-verification of inactive Jan Dhan accounts**
 - **Opening new bank accounts** under the **Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana**
 - **Enrollment in:**
 - **Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)**
 - **Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)**
 - **Atal Pension Yojana (APY)**

Detailed Explanation (For RAS Mains Relevance):



<https://t.me/+9dLgyy8BipQ3YjB>



HYPERLINK
["https://rasonly.com"](https://rasonly.com)
<https://rasonly.com>

- **Objective:** Strengthening the last-mile delivery of financial services and empowering rural citizens economically.
- **Campaign Significance:**
 - Aligns with **UN SDGs** (especially Goal 1 – No Poverty, Goal 8 – Decent Work and Economic Growth).
 - Ensures **universal financial coverage** and **risk protection** through insurance and pension.
- **Role of Stakeholders:**
 - **District Administration:** Responsible for planning and infrastructure.
 - **Banks:** Must ensure account activation, enrollments, and financial literacy.
 - **Panchayats:** Will act as the outreach platform to rural citizens.
- **Schemes Involved:**
 - **PMJDY:** Zero balance accounts for financial inclusion.
 - **PMSBY & PMJJBY:** Social security via insurance (accident and life).
 - **APY:** Pension scheme for unorganised sector workers.
- **Operational Model:**
 - Camps on Saturdays – more public participation.
 - Each village to be covered at least once.
- **Expected Outcomes:**
 - Increase in **active bank accounts**, **insurance coverage**, and **pension scheme subscribers**.
 - Boost in **financial literacy** and **confidence among rural populations**.
- **Link with Rajasthan's rural development:**
 - Enhances existing state-level poverty alleviation and empowerment efforts.
 - Complements schemes like **Deendayal Antyodaya Yojana**, **Mahatma Gandhi NREGA**, etc.

हिंदी अनुवाद

क्षेत्र: वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा

विषय: सरकारी योजनाएं एवं बैंकिंग पहुँच

1 जुलाई से 30 सितंबर तक देशव्यापी वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा अभियान

मुख्य बिंदु:

- भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के निर्देशानुसार **1 जुलाई से 30 सितंबर, 2025 तक देशव्यापी अभियान** चलाया जा रहा है।
- इस अभियान का उद्देश्य **ग्राम पंचायत स्तर तक बैंकिंग, बीमा और पेंशन सेवाएं पहुँचाना** है।
- **प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक विशेष शिविर** आयोजित होगा, मुख्यतः **शनिवार** को।
- **मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत** ने सभी **जिला कलेक्टरों** को जिला स्तरीय बैंकिंग समिति के समन्वय से विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए हैं।



- बैंकों के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं समय पर जुटाने होंगे।
- नागरिकों से सक्रिय भागीदारी की अपील की गई है ताकि वे अपनी और परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें।
- अभियान के अंतर्गत मुख्य गतिविधियाँ:
 - निष्क्रिय जन धन खातों का पुनः सत्यापन।
 - नए बैंक खाते खोलना।
 - योजनाओं में नामांकन:
 - प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
 - प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
 - अटल पेंशन योजना (APY)

विस्तृत व्याख्या (RAS मुख्य परीक्षा हेतु प्रासंगिक):

- उद्देश्य: अंतिम व्यक्ति तक वित्तीय सेवाओं की पहुँच और आर्थिक रूप से सक्षम बनाना।
- अभियान का महत्व:
 - संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) से मेल (लक्ष्य 1 और 8)।
 - सभी के लिए वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित करना।
- प्रमुख भागीदार:
 - जिला प्रशासन – शिविर आयोजन एवं योजना निर्माण।
 - बैंकिंग संस्थाएं – खाता सक्रियता, बीमा/पेंशन नामांकन।
 - ग्राम पंचायतें – जनसंपर्क माध्यम।
- शामिल योजनाएं:
 - PMJDY: शून्य शेष खाता योजना।
 - PMSBY व PMJJBY: बीमा आधारित सामाजिक सुरक्षा।
 - APY: असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना।
- शिविर मॉडल:
 - शनिवार को शिविर – अधिक भागीदारी की संभावना।
 - हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक बार शिविर।
- अपेक्षित परिणाम:
 - सक्रिय बैंक खातों में वृद्धि, बीमा और पेंशन योजनाओं में नामांकन में वृद्धि।
 - वित्तीय साक्षरता में सुधार।

- राजस्थान के ग्रामीण विकास से संबंध:

- राज्य सरकार की योजनाओं जैसे दीनदयाल उपाध्याय योजना, मनरेगा, आदि का पूरक।

MCQs (Multiple Choice Questions)

Question:

Which of the following is *not* a focus area of the nationwide financial inclusion campaign running from July 1 to September 30, 2025?

1. Re-verification of Jan Dhan accounts
2. Opening of new Jan Dhan accounts
3. Sanctioning of MUDRA Loans
4. Enrollment in Atal Pension Yojana

Answer: 3

Explanation: MUDRA Loans are not part of the mentioned components of this specific campaign, which focuses on banking, insurance, and pension schemes.

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था

विषयवस्तु: वित्तीय समावेशन अभियान

प्रश्न:

निम्न में से कौन-सा बिंदु 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2025 तक चलाए जा रहे देशव्यापी वित्तीय समावेशन अभियान का हिस्सा नहीं है?

1. जनधन खातों का पुनः सत्यापन
2. नए जनधन खातों की शुरुआत
3. मुद्रा ऋण की स्वीकृति
4. अटल पेंशन योजना में नामांकन

उत्तर: 3

व्याख्या: इस विशेष अभियान में मुद्रा ऋण शामिल नहीं है, इसका केंद्र बैंकिंग, बीमा व पेंशन योजनाएं हैं।

Question:

Who is responsible for organizing the camps under the nationwide financial inclusion and social security campaign at the district level?

1. Panchayat Secretaries
2. Lead District Managers



3. Regional Managers of Banks
4. Deputy Sarpanch

Answer: 2

Explanation: The campaign will be executed under the leadership of District Collectors, coordinated by the Lead District Manager (LDM).

प्रश्न:

देशव्यापी वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जिला स्तर पर शिविरों का आयोजन किसके समन्वय में होगा?

1. पंचायत सचिव
2. अग्रणी जिला प्रबंधक
3. क्षेत्रीय बैंक प्रबंधक
4. उप सरपंच

उत्तर: 2

व्याख्या: जिला कलेक्टर के नेतृत्व में अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM) इस अभियान में समन्वय भूमिका निभाएंगे।

Rajeev Sharma appointed as new DGP of Rajasthan; to serve a fixed tenure of two years





RAJEEV SHARMA NAMED RAJASTHAN DGP

Sector: Governance & Administration

Subject: State Police Administration / Public Service Appointments

Summary in Bullet Points:

- Senior IPS officer **Rajeev Kumar Sharma** has been appointed as the new **Director General of Police (DGP)** of Rajasthan.
- The appointment came into effect after he was relieved from his posting in Delhi on Wednesday night.
- Formal appointment orders were issued on **Thursday afternoon**, and he took charge at **Police Headquarters** the same evening.
- **CM Bhajanlal Sharma** met the new DGP after the latter assumed office.
- The DGP post became vacant after DGP **U.R. Sahu** took **voluntary retirement on 10 June 2025**, after being made **Chairman of Rajasthan Public Service Corporation (RPSC)**.
- In the interim, **Ravi Prakash Meharda** was appointed **acting DGP**.
- A panel of **6 IPS officers** was sent to **UPSC** by the Personnel Department for selection of the new DGP.
- Although Rajeev Sharma was to retire in **March 2026** upon turning 60, the **Supreme Court mandates a fixed 2-year tenure for DGPs**, meaning he will now serve until **July 2027**.

Detailed Explanation (For RAS Mains Preparation):

- **Constitutional & Legal Provision:**
 - The **Supreme Court in the Prakash Singh Case (2006)** mandated that the DGP of a state must be selected from a panel of the 3 most senior officers shortlisted by the UPSC and shall be given a minimum tenure of 2 years, regardless of the date of superannuation.
- **Administrative Procedure:**



- The Rajasthan government followed due process by forwarding a panel of 6 senior IPS officers to the UPSC for evaluation.
- After due consideration, **Rajeev Sharma** was selected and appointed formally.
- **Tenure and Service Implication:**
 - Though Sharma was due for retirement in March 2026, the Supreme Court's ruling allows an extension until July 2027 to ensure continuity and effectiveness in police leadership.
- **Importance for Governance:**
 - A stable police leadership is crucial for long-term reforms, policy continuity, and effective crime control.
 - This move also strengthens the rule of law by upholding SC-mandated service tenures for top police officials.
- **About Rajeev Kumar Sharma:**
 - A seasoned IPS officer with significant administrative and field experience.
 - His selection reflects both seniority and service record alignment with UPSC guidelines.

क्षेत्र: शासन एवं प्रशासन

विषय: राज्य पुलिस प्रशासन / लोक सेवा नियुक्तियाँ

राजीव शर्मा राजस्थान के नए डीजीपी नियुक्त; दो वर्ष की निश्चित अवधि तक करेंगे सेवा

बिंदुवार संक्षेप:

- वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार शर्मा को राजस्थान का नया पुलिस महानिदेशक (DGP) नियुक्त किया गया है।
- यह नियुक्ति बुधवार रात दिल्ली से कार्यमुक्त होने के बाद प्रभावी हुई।
- गुरुवार दोपहर को औपचारिक नियुक्ति आदेश जारी किए गए और उसी शाम उन्होंने पुलिस मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण किया।
- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यभार संभालने के बाद नए डीजीपी से भेंट की।
- डीजीपी का पद तब खाली हुआ जब डीजीपी यू.आर. साहू ने 10 जून 2025 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली; उन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) का अध्यक्ष बनाया गया।
- इस बीच, रवी प्रकाश मेहरड़ा को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया।
- नए डीजीपी के चयन के लिए कार्मिक विभाग द्वारा 6 आईपीएस अधिकारियों का पैनल यूपीएससी को भेजा गया था।
- यद्यपि राजीव शर्मा मार्च 2026 में 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले थे, परंतु सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार डीजीपी को दो वर्ष की निश्चित अवधि मिलनी चाहिए, जिसके अनुसार अब वे जुलाई 2027 तक सेवा देंगे।



विस्तृत विवरण (RAS मुख्य परीक्षा तैयारी हेतु):

• संवैधानिक एवं विधिक प्रावधान:

o सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार केस (2006) में आदेश दिया था कि राज्य का डीजीपी यूपीएससी द्वारा चयनित 3 वरिष्ठतम अधिकारियों के पैनल से चुना जाए और उसे न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल दिया जाए, भले ही उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि क्या हो।

• प्रशासनिक प्रक्रिया:

o राजस्थान सरकार ने प्रक्रिया का पालन करते हुए 6 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का पैनल यूपीएससी को मूल्यांकन हेतु भेजा।

o सम्यक विचार के पश्चात् राजीव शर्मा का चयन कर औपचारिक रूप से नियुक्ति की गई।

• कार्यकाल एवं सेवा पर प्रभाव:

o यद्यपि शर्मा मार्च 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले थे, परंतु सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जुलाई 2027 तक उनका कार्यकाल बढ़ाया गया जिससे पुलिस नेतृत्व में निरंतरता और प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके।

• शासन के लिए महत्व:

o स्थायी पुलिस नेतृत्व दीर्घकालिक सुधारों, नीति की निरंतरता और प्रभावी अपराध नियंत्रण के लिए आवश्यक है।

o यह निर्णय शीर्ष पुलिस अधिकारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सेवा अवधि का पालन कर कानून के शासन को भी सुदृढ़ करता है।

• राजीव कुमार शर्मा के बारे में:

o एक अनुभवी आईपीएस अधिकारी जिनका प्रशासनिक एवं क्षेत्रीय अनुभव समृद्ध है।

o उनका चयन वरिष्ठता एवं सेवा रिकॉर्ड के साथ यूपीएससी दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

Ask ChatGPT

MCQs

Question: According to the Supreme Court's directive, what is the minimum fixed tenure of a DGP in Indian states?

1. 1 year
2. 2 years
3. Until superannuation
4. As per state's service rules

Answer: 2



Explanation: As per the *Prakash Singh* judgment (2006), a DGP must be given a minimum 2-year fixed tenure.

प्रश्न: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार किसी राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) का न्यूनतम निश्चित कार्यकाल क्या होना चाहिए?

1. 1 वर्ष
2. 2 वर्ष
3. सेवानिवृत्ति तक
4. राज्य सेवा नियमों के अनुसार

उत्तर: 2

व्याख्या: प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार केस (2006) के अनुसार DGP को कम से कम 2 वर्षों का कार्यकाल अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए।

Question: Which authority prepares the final panel for selection of the DGP in states?

1. Ministry of Home Affairs
2. State Public Service Commission
3. UPSC
4. President of India

Answer: 3

Explanation: The UPSC selects the panel of top IPS officers from which the state appoints its DGP.

प्रश्न: राज्य में पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति के लिए अंतिम पैनल कौन तैयार करता है?

1. गृह मंत्रालय
2. राज्य लोक सेवा आयोग
3. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
4. भारत के राष्ट्रपति

उत्तर: 3

व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार DGP के चयन हेतु अंतिम पैनल UPSC द्वारा तैयार किया जाता है।

Judicial Appointments in Rajasthan High Court Strengthened with Two New Names





Sector: Judiciary and Constitutional Bodies

Subject: Indian Polity & Governance – Judiciary System, High Court functioning, Judicial Appointments

Summary of News:

- Supreme Court Collegium has recommended **two names** for appointment as Judges of the Rajasthan High Court:
 - **Advocate Anuroop Singhi**
 - **Judicial Officer Sangeeta Sharma**
- The recommendation has been **forwarded to the Central Government** for formal notification.
- These names were originally sent by the **Rajasthan High Court** itself.
- **Anuroop Singhi:** A senior advocate and former Joint Secretary of High Court Bar Association, Jaipur Bench.
- **Sangeeta Sharma:** Senior-most officer in Rajasthan Judicial Services, 1992 batch topper.
 - Served as District Judge in **Ajmer, Karauli, Merta City, and Alwar**.
 - Also posted in **Jodhpur and several other districts**.

Detailed Explanation for RAS Aspirants:

- **Supreme Court Collegium System:**
 - It is a judicial body responsible for appointments and transfers of judges in High Courts and the Supreme Court.
 - The Collegium for High Court judges includes the **Chief Justice of India** and two senior-most judges of the Supreme Court.
- **Appointment Process:**

1. High Court recommends names.



<https://t.me/+9dLgyy8BipQ3YjB>



HYPERLINK
["https://rasonly.com"](https://rasonly.com)
<https://rasonly.com>

2. Supreme Court Collegium reviews and approves.
 3. Recommendations go to the **Ministry of Law and Justice**.
 4. After President's assent, appointment is notified.
- **Importance of These Appointments:**
 - These appointments address **judicial backlog** and **reduce pendency** in High Courts.
 - The addition of experienced candidates like Sharma and Singhi ensures **quality adjudication**.
 - **Background of Appointees:**
 - *Anuroop Singhi*: Strong background in legal practice, advocate leadership roles.
 - *Sangeeta Sharma*:
 - A topper of Rajasthan Judicial Services (1992).
 - Wide-ranging experience in judicial positions across key districts.
 - **Why Relevant for RAS Mains:**
 - Reflects **judicial functioning and independence**.
 - Important for topics on **separation of powers, Centre-State relations, and judicial administration**.
 - Part of **current affairs-based Indian Polity questions**.

राजस्थान हाईकोर्ट को मिलेंगे दो और नए न्यायाधीश

प्रसंग:

क्षेत्र: न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाएं

विषय: भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन - न्यायिक प्रणाली, उच्च न्यायालय का कार्य, न्यायाधीशों की नियुक्ति

मुख्य बिंदु:

- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट के लिए दो न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की:
 - एडवोकेट अनुरूप सिंघी
 - न्यायिक अधिकारी संगीता शर्मा
- यह सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी गई है।
- इन नामों की सिफारिश स्वयं राजस्थान हाईकोर्ट ने की थी।
- **अनुरूप सिंघी**: वरिष्ठ अधिवक्ता और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (जयपुर पीठ) के संयुक्त सचिव रहे हैं।
- **संगीता शर्मा**:
 - राजस्थान न्यायिक सेवा की 1992 बैच की टॉपर।
 - अजमेर, करौली, मेड़ता सिटी और अलवर में जिला न्यायाधीश रही हैं।



- जोधपुर समेत कई जिलों में कार्यरत रही हैं।

RAS अभ्यर्थियों के लिए संक्षिप्त विश्लेषण:

- **सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम प्रणाली:**
 - यह प्रणाली न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादलों हेतु जिम्मेदार होती है।
 - हाईकोर्ट जजों के लिए कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं।
- **न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया:**
 1. हाईकोर्ट नामों की अनुशंसा करता है।
 2. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम समीक्षा करता है।
 3. नाम विधि मंत्रालय को भेजे जाते हैं।
 4. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी होती है।
- **नियुक्तियों का महत्व:**
 - इससे मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी।
 - अनुभवी न्यायाधीशों की नियुक्ति से गुणवत्ता युक्त न्याय प्रदान संभव होगा।
- **नव नियुक्त व्यक्तियों की पृष्ठभूमि:**
 - अनुरूप सिंघी: वरिष्ठ अधिवक्ता व बार संघ में नेतृत्व अनुभव।
 - संगीता शर्मा:
 - न्यायिक सेवा की टॉपर।
 - बहु-जिलों में न्यायिक सेवाओं का व्यापक अनुभव।
- **RAS मुख्य परीक्षा के लिए प्रासंगिकता:**
 - न्यायपालिका की कार्यप्रणाली और स्वतंत्रता से जुड़ा महत्वपूर्ण बिंदु।
 - वर्तमान घटनाओं से जुड़े राज्यव्यवस्था प्रश्नों में उपयोगी।

MCQs in English and Hindi

Question: Which two individuals were recently recommended by the Supreme Court Collegium for appointment as judges in Rajasthan High Court?

1. Rajeev Sharma and Manju Yadav
2. Anuroop Singhi and Sangeeta Sharma



3. Vikas Joshi and Seema Rathore
4. Shyam Lal and Sadhna Meena

Answer: 2. Anuroop Singhi and Sangeeta Sharma

Explanation: The Supreme Court Collegium has recommended Anuroop Singhi (advocate) and Sangeeta Sharma (judicial officer) for appointment.

राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्ति हेतु हाल ही में किन दो व्यक्तियों की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की?

1. राजीव शर्मा और मंजू यादव
2. अनुरूप सिंघी और संगीता शर्मा
3. विकास जोशी और सीमा राठौर
4. श्याम लाल और साधना मीणा

उत्तर: 2. अनुरूप सिंघी और संगीता शर्मा

व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अधिवक्ता अनुरूप सिंघी व न्यायिक अधिकारी संगीता शर्मा की सिफारिश की है।

Question: Which body is primarily responsible for recommending High Court judge appointments in India?

1. Election Commission of India
2. President of India
3. Supreme Court Collegium
4. Union Public Service Commission

Answer: 3. Supreme Court Collegium

Explanation: The Supreme Court Collegium recommends names to the central government for High Court appointments.

भारत में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली प्रमुख संस्था कौन-सी है?

1. भारत निर्वाचन आयोग
2. भारत के राष्ट्रपति
3. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम
4. संघ लोक सेवा आयोग

उत्तर: 3. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करता है।

India Shines at World Police Games: Rajasthan's Kachnar and Dilip Bag Gold Medals



Sector: Sports Sector (Police and Paramilitary Sports Achievements)

Subject: Rajasthan Police and CRPF Performance in International Sports Events

- The World Police and Fire Games are being held in Birmingham, Alabama (USA) from 27 June to 7 July 2025.
- Sub-Inspector **Kachnar Chaudhary** of Rajasthan Police won **Gold in Shot Put** and **Silver in Discus Throw**.
- Kachnar has been training at Reliance Sports Foundation, Mumbai.
- Dilip Kumar Malav from CRPF, hailing from Jhalawar, Rajasthan, won **Gold in Karate**.
- Dilip defeated Malaysia in the semi-final and Romania in the final.
- A total of **70 countries** are participating in the games.
- Rajasthan Police has **10 selected athletes** representing in the games.
- Kachnar expressed gratitude towards Rajasthan Police and DG Anand Srivastava for their support.
- Dilip's teammates included Mahendra Yadav, Anil Sharma, and Ajay Thangchan.
- Member of Parliament Dushyant Singh congratulated Dilip on his achievement.

Detailed Explanation (Important for RAS Mains):

- **World Police and Fire Games (WPFG):** A biennial event that brings together serving and retired police and fire personnel from around the globe.
- **Significance for Rajasthan:**
 - Demonstrates Rajasthan Police's commitment to physical excellence and international sports participation.



<https://t.me/+9dLgyy8BipQ3YjB>



HYPERLINK
["https://rasonly.com"](https://rasonly.com)
<https://rasonly.com>

- Shows the outcome of institutional support and private training collaboration (e.g., Reliance Sports Foundation).
- **Institutional Encouragement:**
 - Rajasthan Police's consistent support underlines a growing focus on holistic development of its personnel.
- **Women's Achievement:**
 - Kachnar's medal-winning performance highlights increasing representation and success of women officers in global sporting events.
- **International Exposure:**
 - Participation in global events enhances soft diplomacy and builds international camaraderie among uniformed forces.
- **Strategic Sports Planning:**
 - Collaboration between state departments and sports foundations is essential for talent grooming and performance.

हिन्दी अनुवाद

खेल क्षेत्र (पुलिस और अर्धसैनिक खेल उपलब्धियाँ)

विषय: अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस और सीआरपीएफ का प्रदर्शन

वर्ल्ड पुलिस गेम्स में भारत की चमक: राजस्थान की कचनार और दिलीप ने जीते गोल्ड मेडल

- अमेरिका के अलबामा प्रांत के बर्मिंघम शहर में 27 जून से 7 जुलाई 2025 तक वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं।
- राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर **कचनार चौधरी** ने **शॉट पुट** में **स्वर्ण पदक** और **डिस्कस थ्रो** में **रजत पदक** जीता।
- कचनार मुंबई स्थित रिलायंस स्पोर्ट्स फाउंडेशन में प्रशिक्षण ले रही थीं।
- झालावाड़ निवासी सीआरपीएफ के **दिलीप कुमार मालव** ने **कराटे** में **स्वर्ण पदक** प्राप्त किया।
- दिलीप ने सेमीफाइनल में मलेशिया और फाइनल में रोमानिया को हराया।
- इस प्रतियोगिता में **70 देशों** के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।
- राजस्थान पुलिस के **10 खिलाड़ियों** का चयन इन खेलों के लिए हुआ है।
- कचनार ने राजस्थान पुलिस विभाग और डीजी आनंद श्रीवास्तव के सहयोग के लिए आभार जताया।
- दिलीप के टीम सदस्य महेन्द्र यादव, अनिल शर्मा, अजय थंगचन रहे।
- सांसद दुष्यंत सिंह ने दिलीप को शुभकामनाएँ दी।

विस्तृत व्याख्या (आरएस मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु):

- **वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स (WPFG):** यह द्विवर्षीय आयोजन है जिसमें पुलिस और अग्निशमन सेवाओं के सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मचारी भाग लेते हैं।



- राजस्थान के लिए महत्व:

- यह राजस्थान पुलिस के कर्मियों की शारीरिक दक्षता और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भागीदारी को दर्शाता है।
- सरकारी विभाग और निजी प्रशिक्षण संस्थानों (जैसे रिलायंस फाउंडेशन) के सहयोग से अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं।

- संस्थागत सहयोग:

- राजस्थान पुलिस द्वारा खिलाड़ियों को मिल रहा सहयोग एक समग्र विकास दृष्टिकोण को दर्शाता है।

- महिला उपलब्धि:

- कचनार की सफलता महिला अधिकारियों की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ती भागीदारी को रेखांकित करती है।

- अंतर्राष्ट्रीय अनुभव:

- इस तरह के वैश्विक आयोजन सॉफ्ट डिप्लोमेसी को बढ़ावा देते हैं और समान पोशाकधारी बलों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं।

- खेलों की रणनीतिक योजना:

- राज्य विभागों और खेल फाउंडेशनों के बीच समन्वय प्रतिभाओं को निखारने और प्रदर्शन सुधारने में सहायक होता है।

MCQs

Question: Where were the World Police and Fire Games 2025 held?

1. Houston
2. Birmingham
3. Atlanta
4. New York

Answer: 2. Birmingham

Explanation: The 2025 edition of the World Police and Fire Games was hosted in Birmingham, Alabama, USA.

प्रश्न: वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुए?

1. ह्यूस्टन
2. बर्मिंघम
3. अटलांटा



4. न्यूयॉर्क

उत्तर: 2. बर्मिंघम

व्याख्या: वर्ष 2025 के वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का आयोजन अमेरिका के अलबामा राज्य के बर्मिंघम शहर में हुआ।

Question: Which two events did Rajasthan Police's Kachnar Chaudhary win medals in during the World Police Games 2025?

1. High Jump and Long Jump
2. Shot Put and Discus Throw
3. Javelin and Pole Vault
4. Relay Race and Hammer Throw

Answer: 2. Shot Put and Discus Throw

Explanation: Kachnar Chaudhary won Gold in Shot Put and Silver in Discus Throw at the 2025 World Police Games.

प्रश्न: राजस्थान पुलिस की कचनार चौधरी ने वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2025 में किन दो प्रतियोगिताओं में पदक जीते?

1. हाई जंप और लॉन्ग जंप
2. शॉट पुट और डिस्कस थ्रो
3. जेवलिन और पोल वॉल्ट
4. रिले रेस और हैमर थ्रो

उत्तर: 2. शॉट पुट और डिस्कस थ्रो

व्याख्या: कचनार चौधरी ने वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2025 में शॉट पुट में स्वर्ण और डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीते।

1. Sector: Environment & Governance

Subject: Plantation Campaign – Digital Integration in Environmental Initiatives

Mission Hariyalo Rajasthan: Plant Distribution Begins with Online Booking Facility

- Under the *Mission Hariyalo Rajasthan*, the Forest Department has started distributing plants during the monsoon season.
- Over **41.40 lakh saplings** have been prepared across **34 nurseries in Jaipur district**.
- Citizens can **book plants online** via the portal: <https://aaranyak-forest-rajasthan-gov-in>.
- Nurseries are equipped with **QR codes** for on-the-spot selection and payment of saplings.



<https://t.me/+9dLgyy8BipQ3YjB>



HYPERLINK
"https://rasonly.com"htt
ps://rasonly.com

- **Step-by-step process** for online booking:
 - Visit portal and click on **Buy Plant**.
 - Use **Locate Nearby Nursery** or choose a nursery by district.
 - Check available species and stock.
 - Enter required quantity and **Add to Cart**.
 - Login using **SSO ID**, make payment via **Buy Now**, and collect plants using the payment receipt.
- QR codes in nurseries display real-time stock; plants can also be selected and paid for on-site.
- **Signboards** display plant rates, nursery in-charge, and forest officer contact details.
- Citizens can upload plantation proof on the **Hariyalo Rajasthan mobile app** to get a **certificate of plantation**.

Detailed Explanation for RAS Mains (Important Points):

- **Mission Hariyalo Rajasthan** is an annual green initiative by the Rajasthan Forest Department, supported by Rajasthan Patrika, launched formally in 2005.
- It promotes **community participation in afforestation**.
- In 2025, digital features like **online booking, QR-coded nurseries, and mobile app tracking** have been added.
- Promotes **transparency, efficiency, and public engagement** using technology.
- The initiative supports **climate change mitigation, biodiversity preservation, and urban greening**.
- Useful in writing answers related to:
 - **Environment & Ecology**
 - **Digital Governance**
 - **Public Participation in Policy Implementation**
- The plantation certificate serves as a form of **citizen incentivization and behavioral nudge** towards eco-conscious behavior.

राजस्थान मिशन हरियालो के तहत पौध वितरण प्रारंभ, ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध

- मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत मानसून में वन विभाग ने पौध वितरण शुरू कर दिया है।
- जयपुर जिले की 34 नर्सरियों में 41.40 लाख से अधिक पौधे तैयार किए गए हैं।
- आमजन <https://aaranyak-forest-rajasthan-gov-in> पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पौध बुकिंग कर सकते हैं।
- नर्सरियों में **क्यूआर कोड** की व्यवस्था भी की गई है, जिससे मौके पर ही भुगतान कर पौध लिए जा सकते हैं।
- **ऑनलाइन प्रक्रिया:**
 - पोर्टल पर जाकर **Buy Plant** विकल्प चुनें।
 - **Locate Nearby Nursery** या जिला चुनकर नर्सरी ढूंढें।



- पौधों की प्रजाति व संख्या देखकर आवश्यकता अनुसार **Add to Cart** करें।
- **SSO ID** से लॉगिन कर **Buy Now** पर भुगतान करें।
- भुगतान रसीद दिखाकर पौधे प्राप्त करें।
- क्यूआर कोड स्कैन कर स्टॉक देखा जा सकता है; **साइनेज बोर्डों** में दरें, प्रभारी, और अधिकारियों के नंबर उपलब्ध हैं।
- **हरियालो राजस्थान मोबाइल ऐप** पर फोटो अपलोड कर **प्रशस्ति पत्र** प्राप्त किया जा सकता है।

विस्तृत व्याख्या (RAS मुख्य परीक्षा हेतु):

- *मिशन हरियालो राजस्थान* वर्ष 2005 से राजस्थान पत्रिका के सहयोग से चलाया जा रहा एक सामुदायिक हरियाली अभियान है।
- यह राज्य में **जन सहभागिता से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित** करता है।
- 2025 में इस अभियान को **डिजिटल तकनीकों** से जोड़ा गया है—ऑनलाइन बुकिंग, क्यूआर कोड, और मोबाइल ऐप।
- यह पहल **पारदर्शिता, लाभार्थी ट्रेकिंग और तकनीकी नवाचार** का उदाहरण है।
- यह प्रयास **जलवायु परिवर्तन नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण, और नागरिक सहभागिता** की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह पहल **ई-गवर्नेंस, सार्वजनिक सेवाओं का डिजिटलीकरण, और जन जागरूकता अभियान** जैसे विषयों से जुड़ी है।

MCQs (English then Hindi):

Question: Which digital feature has been introduced in the 2025 phase of *Mission Hariyalo Rajasthan* to increase citizen convenience and transparency in plant distribution?

1. GPS monitoring of plantations
2. E-auction of saplings
3. QR codes in nurseries and online booking system
4. Biometric verification of planters

Answer: 3

Explanation: QR codes and online booking via the Aaranyak portal were introduced to streamline the plant distribution process.



मिशन हरियालो राजस्थान के 2025 चरण में पौध वितरण में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने हेतु कौन-सी डिजिटल सुविधा जोड़ी गई है?

1. पौधों की GPS निगरानी
2. पौधों की ई-नीलामी
3. नर्सरी में क्यूआर कोड और ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली
4. पौधा लगाने वालों की बायोमेट्रिक पहचान

उत्तर: 3

व्याख्या: पोर्टल आधारित ऑनलाइन बुकिंग और नर्सरी में क्यूआर कोड व्यवस्था से वितरण में सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई।

